Highway was not found to be a fairweather road and therefore, causes great inconvenience to passengers etc;

- (c) whether Government have considered the proposal; and
- (d) if so, whether Government propose to construct the Moghal Road as an alternative to present National Highway?

MINISTER OF SHIPPING AND TRANSPORT (SHRI K. VIJAYA BHASKARA REDDY): (a) to (d), The proposed road when constructed would be a State road. The Jammu & Kashmir Government are, therefore, primarily concerned in the matter. Sometime back they sent a proposal for this road to provide an additional link to Kashmir Valley and also to provide direct access from Rajouri and Poonch district Srinagar. The Central Government have, no objection to the State Government's proposal if they finance it from their own resources. The State Government have been asked to carry out detailed engineering and feasibility studies for finalisation of the alignment and location with a tunnel, if necessary at a lower altitude to make it all weather road. They have also been asked to refer Central Government for approval the specifications of the tunnel and the final alignment before undertaking the project. There has been no further response from the State Government so far.

पश्चिम जर्मनी में दूरदर्शन पर प्रधानमन्त्री के बारे में टिप्पणियां

*279. श्री सुभाष यादव: श्री माधवराव सिंधिया:

वया विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 13 फरवरी, 1984 के "नवभारत टाइम्स" में छपे उस समाचार की ओर दिलाया गया

- है, जिसमें कहा गया है कि पश्चिम जर्मनी के एक दूरदर्शन प्रसारण में 5 फरवरी, 1984 को भारत के प्रधानमन्त्री की कटु आलो-चना को गई है और आधारहीन आरोप लगाए गए हैं ;
- (ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में पश्चिम जर्मनी की सरकार से विरोध प्रकट किया है:
- (ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं : और
- (घ) इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है ?

विवेश मन्त्री (श्री पी०वी० नर्रासह राव): (क) से (ध) सरकार ने यह खबर देखी है। यह नःमला जर्मन संघीय गणराज्य के सम्बन्धित प्राधिकारियों के साथ उठाया गया है।

निराश्रित बच्चों के लिए बाल गृहों का निर्माण

*280. श्री दिलीप सिंह भूरिया: क्या समाज कल्याण मन्त्री यह बतान की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या निराश्रित बालकों के लिए केन्द्रीय सहायता, योजना के अन्तर्गत बाल गृहों के निर्माण के लिए 40,000 रुपये की सहायता राशि पर्याप्त है ;
- (ख) क्या इस मद के अन्तर्गत पर्याप्त सहायता न मिलने के कारण मध्य प्रदेश में अनेक बाल गृह अधूरे पड़े हुए हैं ;
- (ग) यदि हां, तो क्या इन अध्रे गृहों को परा करने के लिए अतिरिक्त सहायता दिए जाने का कोई प्रस्ताव है : और
- (घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?